VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time Allowed: ***Three Hours***

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 0356415

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : MOHAN LAL

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English
हिंदी

तारीख
Date
26-Aug. 2023

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre Jaipur

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

VISIONIAS

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

VISION IAS

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use

परीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Examiner(s)

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ **Marks Details (To be filled by the Examiner(s))**

प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**		प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**	
1			**11**		
2			**12**		
3			**13**		
4			**14**		
5			**15**		
6			**16**		
7			**17**		
8			**18**		
9			**19**		
10			**20**		
उप-योग (A) **Subtotal (A)**			उप-योग (B) **Subtotal (B)**		
सकल योग (A+B) / **GRAND TOTAL (A+B)**					

VISION IAS

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (2423)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे Time Allowed: **Three** Hours	अधिकतम अंक: **250** Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

VISION IAS

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS

1. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से, चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत में पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी और अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
With suitable examples, discuss how environmental pressure groups enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पर्यावरणीय दबाव समूह गैर-राजनीतिक प्रकृति के ऐसे समूह हैं जो नीति-निर्माण, निर्णय प्रक्रिया में पर्यावरणीय संधारणीयता की वकालत करते हैं।

EPG का पर्यावरण नीतियों में योगदान

(A) सार्वजनिक भागीदारी हेतु :

→ स्थानीय जनता को शामिल करना।
Exp → EIA (पर्यावरण प्रभाव आंकलन) हेतु 'पर्यावरण बचाओ' अभियान
→ पर्यावरणीय प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना
(उदा०) बाबा आम्टे द्वारा महाराष्ट्र में आंदोलन
→ ग्रीनपीस इण्टरनेशनल द्वारा असम कोल फील्ड हेतु दबाव बनाना

(B) अनुक्रियाशीलता हेतु

① पर्यावरणीय क्षरण के प्रति सरकार पर दबाव ⇒ उदा० सरदार बांध गुजरात

② पुनर्स्थापना तथा पुनर्बहाली हेतु :

EPG के दबाव से ही CAMPFA-2016 की स्थापना की गई

③ सामुदायिक भागीदारिता बढ़ाने में

उदा० - उत्तराखंड में वृक्ष बचाओ अभियान

④ सरकार पर दबाव द्वारा :

इसी कारण 1986 का EPA अधिनियम, CRZ-2011, प्लास्टिक विनियम इत्यादि पारित

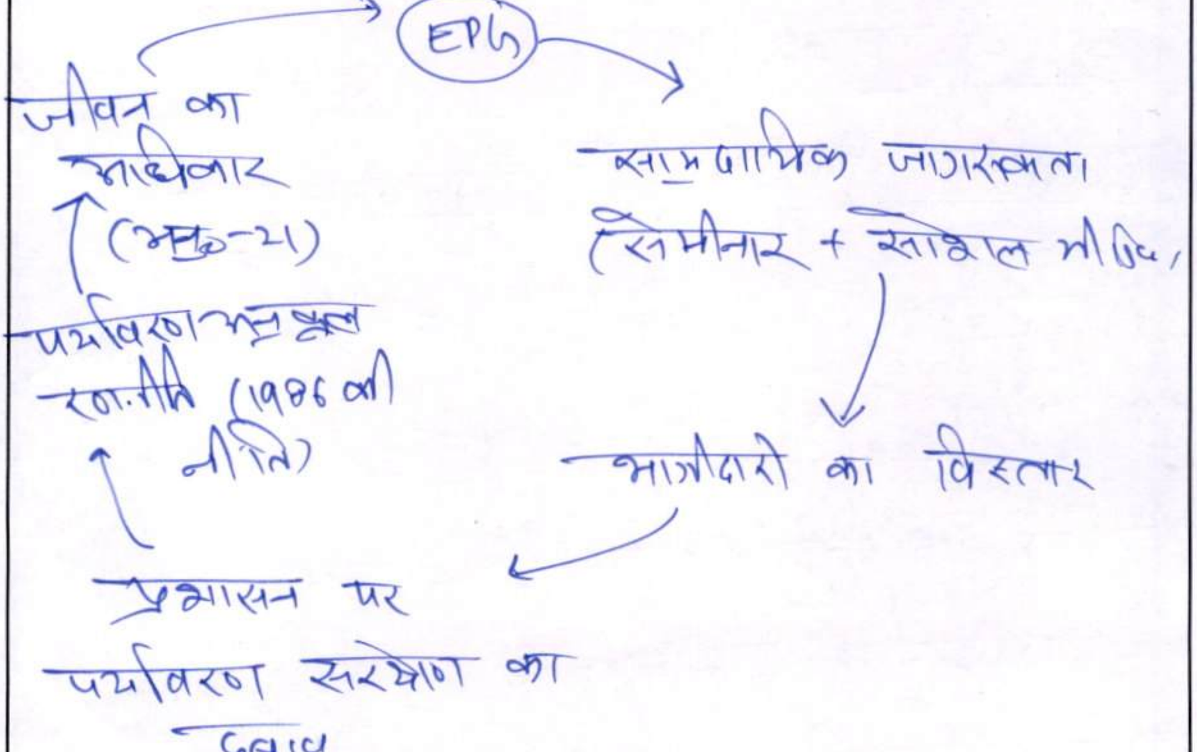

अतः EPG दबावकर्ता के साथ-साथ अनुक्रियाशीलता, जवाबदेहिता तथा लक्ष्य आधारित भागीदारी में सक्रिय भूमिका निभाता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2. हाल ही में, उच्चतम न्यायालय द्वारा सेक्स वर्क को एक 'पेशे' के रूप में स्वीकार किया जाना, भारत में सेक्स वर्कर्स के लिए बुनियादी अधिकार और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The recent acknowledgment of sex work as a 'profession' by the Supreme Court is merely the first step in ensuring basic rights and equality for sex workers in India. Examine. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय समानता, समावेशिता, न्याय का समोचित वितरण तथा सार्वभौमिकता जैसे सिद्धांतो के अनुकूल हैं।

सेक्स वर्कर्स हेतु पूर्व धारणा:..

प्रतिबंध + IPC के तहत अपराध + सामाजिक कलंक

SC की व्याख्या।

बुनियादी अधिकारों को मान्यता: (सेक्स वर्कर्स)

① अनु० 14 के तहत समानता का अधिकार

② विभेद का प्रतिषेध (अनु० 15)

पेशे के आधार पर भेद नहीं

मानवीय दृष्टिकोण

③ जीवन जीने का अधिकार (अनु० 21)

गरिमामय जीवन

(उदा० - गंगूबाई काठियावाड़ी)

(ii) व्यापार या पेशे का मौलिक अधिकार (अनु० 19) ⇒ पेशे को अपनाना अपराध नहीं

इससे समानता प्राप्त करने में निम्नलिखित सहायता मिलेगी

- → समावेशिता
- → मुख्य धारा में जुड़ना
- → सामाजिक कलंक निवारण
- → पेशे, स्वच्छता तथा जीवन का अधिकार

चुनौतियाँ

- → विधिक संरक्षण का अभाव (कोई कानून नहीं)
- → पारंपरिक मूल्यों पर आधारित समाज में अमान्यता
- → कलंक तथा आर्थिक-सामाजिक सुविधा तक निम्न पहुँच

आगे की राह

- → सामाजिक न्याय मंत्री की अध्यक्षता में सेक्स वर्कर्स परिषद, बोर्ड व कोष का गठन
- → सामाजिक गतिशीलता बढ़ाना
- → समावेशिता हेतु कार्यक्रमों से जोड़ना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

3. भारत में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने और कानूनी जागरूकता फैलाने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (DLSAs) द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Discuss the role played by District Legal Services Authorities (DLSAs) in providing free legal aid and disseminating legal awareness in India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

NALSA अधिनियम 1987

के तहत जिला स्तर पर DLSA (जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों) की स्थापना की गई है।

वर्तमान में कार्यरत DLSA = 700 से अधिक

DLSA की नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में भूमिका

① पिछड़े वर्गों की न्याय तक निष्पक्ष तथा सुलभ पहुँच
- → PWD, बच्चे महिला
- → OBC (1 लाख आय तक)
- → संघर्ष में शामिल व्यक्ति इत्यादि

② वहनीय न्याय :-

अनुच्छेद 39A के लक्ष्यों तथा न्याय हेतु नि:शुल्क विधिक सहायता देना।

③ कानूनी जागरूकता फैलाना :-

उदा०- महाराष्ट्र SALSA ने सेमिनार तथा न्याय आपके द्वार कार्यक्रम द्वारा जागरूकता

④ राज्य के कर्तव्य के रूप में :-

यह अनुच्छेद 37 के तहत राज्य का कर्तव्य भी है।

⑤ समावेशी न्यायिक समाज का निर्माण

जैसे- निःशुल्क प्रतियाँ व वकील उपलब्ध कराना

अन्य महत्व — प्रशासन का जनो-मुखीकरण
→ भागीदारिता का विस्तार
→ न्याय (प्रशासनिक) में विश्वास।

कुछ चुनौतियाँ

→ विधिक कार्यवाही में उच्च समय
→ DLSAs में मानव संसाधनों की कमी (ADR रिपोर्ट के अनुसार यह कुछ राज्यों में 40% तक है)
→ e-तकनीकी का अभाव

क्या किया जाना चाहिए

→ समलैंगिकों, श्रमिकों तथा किसानों को NALSA में शामिल कर समावेशी बनाना
→ PWD हेतु 'न्याय आपके परिसर' तथा ADR (वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली) को NALSA से जोड़ना।

4. "कुछ लोगों के हाथों में शक्ति के संकेंद्रण के कारण, कॉलेजियम प्रणाली अपनी ही सफलता का शिकार हो गई है, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठने लगे हैं।" टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"The collegium system has become a victim of its own success, with the concentration of power in the hands of a few, leading to questions about its legitimacy." Comment. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट न्यायधीशों की नियुक्ति, ट्रांसफर तथा पदोन्नति हेतु 3rd जज केस 1998 (तीन जज) में कॉलेजियम व्यवस्था अपनाई गई।

कॉलेजियम व्यवस्था

→ सुप्रीम कोर्ट जज हेतु ⇒ CJI + 4 वरिष्ठतम जज द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश

→ हाईकोर्ट जज :- CJI + 2 वरिष्ठतम + HC के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

इसमें कमियाँ

① शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध (न्यायधीश द्वारा न्यायाधीश चुनना)

② भाई-भतीजावाद की समस्या (शक्ति के संकेंद्रण के कारण)

③ पारदर्शिता की कमी: न तो RTI के अंतर्गत और न ही कार्यवाही को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना

④ जवाबदेहिता का अभाव :- संविधान मे इसके हेतु ठोस उपबंध नहीं

⑤ समावेशिता की कमी :-

30% महिला CJI अभी तक न बनना तथा SC/ST व OBC का प्रतिनिधित्व 15% तक ही

⑥ शक्ति संतुलन के विरुद्ध

इस व्यवस्था का लाभ

→ राजनीतिक हस्तक्षेप न होना

→ कार्यपालिका - न्यायपालिका मे पृथक्करण

→ स्वतंत्र न्यायपालिका मौलिक ढाँचे का भाग (IV[th] जजेज केस -2015)

→ तानाशाही कार्यकारी कृत्यों का असंवैधानिकरण करना।

आगे की राह

→ फ्रांस की तर्ज पर NJAC का गठन कर शक्ति संतुलन बनाना

→ वीटो शक्ति CJI को देना

→ जज नियुक्ति व पदोन्नति के कारणों को सार्वजनिक करना,

→ संवैधानिक सर्वोच्चता बनाए रखना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

5. "सिविल सेवा सुधारों को वर्तमान दौर की चुनौतियों से निपटने के लिए भर्ती और मानकीकृत प्रशिक्षण से आगे बढ़ाया जाना अनिवार्य है।" विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
"Civil services reforms must go beyond recruitment and standardised training to cope with the present day challenges." Analyse. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

लोक नीतियों के क्रियान्वयन, प्रत्यायोजित शक्तियों द्वारा लोक कल्याण के रूप में सिविल सेवक लोक-कल्याणकारी राज्य के प्रेरक स्तंभ है।

वर्तमान दौर की चुनौतियाँ

① तकनीकी चुनौती
- → आतंकवाद
- → असुरक्षा
- → भ्रष्टाचार

} डीप वेब, डार्कनेट का प्रयोग
⇓
पारंपरिक सेवकों को कम जानकारी

② बदलता सामाजिक परिवेश

↓ उच्च गतिशीलता
↓ वैश्वीकरण का प्रभाव
↓ समाज का डिजिटलीकरण

⇓

नई सामाजिक चुनौतियों का उदय जैसे- संगठित अपराध; सीमा पार अपराध आदि

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अन्य चुनौतियाँ
- ब्रिटिश औपनिवेशिकता
- नवाचार के प्रति शून्य
- सामान्यवादी स्तर
- आदेश की एकता व लचीलेपन का अभाव

निपटने हेतु उपाय

पारंपरिक उपाय :-
- भर्ती मेरिट बेस (Art-312)
- प्रशिक्षण (LBSNAA)
- सेमिनार तथा फील्ड दौरे।

वर्तमान आवश्यकता
- विशेषज्ञता आधारित दृष्टिकोण अपनाना (जैसे 2nd ARC की मिड कार्यकाल रणनीति)
- तकनीकी प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण (जैसे- मिशन कर्मयोगी)
- नव लोक प्रबंधन (NPM व NPA) आधारित '3E' प्रणाली (मितव्ययता, प्रभाविता तथा दक्षता) अपनाना
- लैटरल एंट्री द्वारा विशेषज्ञता बढ़ाना

हालांकि इसके बावजूद एक कैडर आधारित भर्ती प्रक्रिया समानता (अनु० 15 & 16) तथा न्याय की स्थापना में अधिक प्रभावशील होगी

6. सामाजिक प्रभाव बॉण्ड्स जैसे परिणाम-आधारित वित्त मॉडल में वास्तविक रूप से परिवर्तन लाने और बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता विद्यमान है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
Outcome-based finance models such as social impact bonds have the potential to truly catalyse change and deliver socio-economic impact at scale. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

सामाजिक प्रभाव बॉन्ड्स (SIBs) ऐसे बाण्ड है जिनमें सामाजिक सेवाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन) के विकास हेतु निवेश प्राप्ति की जाती हैं।

SIBs के लाभ

① परिणाम आधारित वित्तीय मॉडल
↓
निवेश ∝ परिणाम (उच्च रिटर्न)

② सरकार पर जन कल्याणकारी व्यय कम ⇒ राजस्व को पूँजीगत व्यय में बदलना ⇒ उच्च आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित

③ लोक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल

④ CSR के विकल्प के तौर पर

⑤ स्वास्थ्य अवसंरचना विकास
↓
UHR (सार्वभौमिक स्वास्थ्य अधिकार) की प्राप्ति।

⑥ क्राउडिंग आउट प्रभाव नहीं :.

निजी निवेश (↑) ⇒ सामाजिक- आर्थिक विकास (↑)

चुनौतियाँ —
- → कम निवेश। (SEBI द्वारा हाल में पहला SIB जारी → NSE पर)
- → विश्वास की कमी (पूंजी बाजार में उच्च रिटर्न)
- → संस्थागत प्रयास में कमी

आगे की राह
- → रिटर्न को तिमाही आधारित देना।
- → न्यूनतम लाभ की सुनिश्चितता।
- → पेंशन फण्ड को SIB में निवेश कर लोगों में विश्वास सृजन करना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. प्रत्येक वर्ष ग्रेजुएट होने वाली और कार्यक्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाओं की संख्या के मध्य का व्यापक अंतराल एक गंभीर समस्या है जिसे हल किए जाने की आवश्यकता है। भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The wide gap between the number of females graduating every year and those entering the workspace is an issue of paramount importance that needs to be addressed. Discuss in the context of India. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

भारत में PLFS-2021 सर्वे के अनुसार महिला कार्यबल भागीदारी दर केवल 27% ही है जो ग्रेजुएशन व कार्य प्राप्ति में व्यापक अंतराल दिखाता है।

इसके प्रमुख कारण

① सुरक्षा का अभाव (कार्यस्थल पर)

② बाल विवाह उच्च (करीब 15% MoWCD के तहत)

③ पितृसत्तात्मक समाज :- पूर्वाग्रह की धारणा।

④ पारिवारिक जिम्मेदारी :- (वृद्ध केयर इकोनॉमी तथा बालपन हेतु)

⑤ उद्यमशीलता का अभाव

⑥ इंडस्ट्री - शिक्षा - रोजगार में व्याप्त अंतराल

समाधान हेतु — अंतराल को हल करने हेतु

दीर्घकालीन रणनीति	तत्कालिक रणनीति
① शिक्षा के व्यावसायिकरण तथा वोकेशनल प्रशिक्षण द्वारा रोजगार से लिंक करना (NEP-2020)	① कौशल प्रशिक्षण में महिला भागीदारी बढ़ाना (India-स्किल रिपोर्ट के अनुसार केवल 8-10% ही कौशल)
② सामाजिक गतिशीलता बढ़ाना ⇒ रोल मॉडल द्वारा उदा० 2000 से 2020 में पिंक कॉलर जॉब में भागीदारिता का विस्तार	② रोजगार व्यवस्था (उदा० राज्यों द्वारा 30% आरक्षण)
③ महिला रोल मॉडल (उदा० रमा देवी द्वारा ग्रामीण विकास चेतना संस्थान	③ उद्यमशीलता बढ़ाना जैसे- स्टैंड अप इण्डिया योजना।
	④ कार्यस्थल सुरक्षा (POSH-2013) के तहत ICC गठन

इस प्रकार महिला कार्यबल में समानता सुनिश्चित करें तो IMF के अनुसार भारत की 23% GDP बढ़ सकती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

8. भारत में सामाजिक-आर्थिक नियोजन के लिए एक अद्यतित और कार्यात्मक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) अनिवार्य है। देश में CRS प्रणाली में सुधार हेतु केंद्र सरकार के हालिया कदम के आलोक में चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

An up to date and functional Civil Registration System (CRS) is essential to the socio-economic planning in India. Discuss in the light of the recent move of the Central government in revamping the CRS system in the country. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margi

नागरिक पंजीकरण प्रणाली में नागरिक जन्म प्रमाण, मृत्यु प्रमाण, मूल निवास जैसी पंजीकरण प्रक्रियाएँ शामिल होती है।

विधिक प्रावधान :- भारतीय नागरिक पंजीकरण अधि.- 1970

इसमें चुनौतियाँ

- आंकड़ो की व्यापकता तथा आभिसरण (अशुद्धि अधिक)
- निरन्तर प्रगतिशील प्रक्रिया नहीं
- तकनीकी का प्रयोग नहीं
- डेटा रिपोजटरी का अभाव
- समय पर अपडेशन नहीं

⇓

मृत्यु के बाद भी मतदाता, योजनाओं का लाभार्थी बना रहना

इस हेतु हालिया सुधार

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

① CRS प्रणाली का डिजिटलीकरण :-
रजिस्ट्रार (MoHA) द्वारा डाटा की रियल टाइम निगरानी

② आधार से लिंक करना
⇓
आंकड़ों में दोहराव नहीं ⇒ नियोजन अधिक लक्षित ⇒ सामाजिक - आर्थिक प्रभाव उच्च

③ राज्य वार प्रणालियों का संयोजन कर केन्द्रीकृत डाटा प्रणाली का विकास करना।

④ जन्म, मृत्यु व मूल निवास प्रमाण पत्र हेतु 24x7 ऑनलाईन सुविधा

इस प्रकार CRS की प्रणाली के आधुनिकीकरण से नीति निर्माण तथा नियोजन में अधिक वास्तविकता आएगी तथा सब्सिडी लिकेज भी कम होगा।

9. यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) को वर्तमान आर्थिक वास्तविकताओं के साथ समायोजित होना है तो इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र कौन-से होंगे? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

What are the key areas of reform if the International Monetary Fund (IMF) has to align with the current economic realities? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

IMF एक ब्रेटन वुड्स संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में वैश्विक मुद्रा स्थिरता तथा व्यापार संतुलन व स्थिरता के उद्देश्य से की गई।

IMF में उभरते मुद्दे

① कोटा प्रणाली :-
मतदान प्रणाली में विकसित देशों का प्रभुत्व अधिक

② ग्लोबल साउथ की निम्न भागीदारी

③ ट्रेंच रिजर्व तथा SDR बास्केट में समावेशिता की कमी

④ संप्रभुता पर अतिक्रमण

⑧ एक विचारधारा (पूँजीवाद) के प्रति झुकाव अधिक

⑥ वर्तमान समस्या (covid-19, SCR) में अप्रभावी भूमिका

इसमें सुधार के प्रमुख क्षेत्र

प्रमुख क्षेत्र	क्या सुधार हो सकता है?
① मतदान प्रणाली व कोटा सिस्टम	→ GDP, प्रतिव्यक्ति आय के साथ खुशहाली इंडेक्स तथा प्राकृतिक संसाधनों को शामिल करना
② BOP संतुलन हेतु ऋण शर्तें	→ देश की नीतियों के अनुकूल हो।
③ नए रिजर्वों की स्थापना।	→ CRF (आकस्मिक रिजर्व फंड) के साथ महामारी फंड का निर्माण
④ ग्लोबल साउथ की भागीदारी बढ़ना।	→ क्षेत्रीय आधार पर कोटा प्रणाली अपनाना।

इस तरह IMF में वर्तमान आर्थिक चुनौतियों से निपटने हेतु बहुपक्षवाद तथा सुधार की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. हाल के वर्षों में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध भू-राजनीति के दायरे से आगे निकलकर भू-अर्थशास्त्र के आयाम तक पहुंच गए हैं। विवेचना कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
In recent years, India's relationship with West Asia has evolved from the confines of geopolitics to expanse of geoeconomics. Discuss. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margi

भारत ने UAE के साथ CECPA समझौता किया है जो दिखाता है कि भू-अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पश्चिमी एशिया का महत्व बढ़ा है।

पहले के संबंध — भू-राजनीतिक स्तर पर

जैसे —
- → अरब देशों में राजनीतिक स्वतंत्रता
- → इजरायल तथा फिलिस्तीन के मुद्दे पर द्विराष्ट्र-सिद्धांत
- → भारत-UAE-सऊदी अरब भू-राजनीतिक गठजोड़

वर्तमान में भू-अर्थशास्त्र तक संबंधों का अभिसरण।

प्रमुख कारण —
- → ऊर्जा सुरक्षा
- → क्रूड ऑयल व रिजर्व हेतु
- → प्राकृतिक संसाधनों हेतु
- → तकनीकी निवेश हेतु घोषणा (भारत में $100 बिलियन की सऊदी अरब

भू- अर्थशास्त्र आयाम के उदाहरण

- काफाला सिस्टम में लोचशीलता
- Ind- UAE- CEPA
- Ind- सऊदी अरब निवेश समझौता
- भारत- ईरान तेल समझौता
- भारत- इजरायल नव तकनीकी (कृषि तथा विलवणीकरण) MOU
- भारत- ओमान लोजिस्टिक बंदरगाह समझौता

इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय निवेश संधियाँ भी महत्वपूर्ण आयाम है जो भू- अर्थशास्त्र के महत्व को दर्शाती है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

11. हितधारकों को नवाचार और प्रभावशीलता में वृद्धि हेतु प्रेरित करने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की भूमिका महत्वपूर्ण है। टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The role of the Competition Commission of India (CCI) is significant in furthering healthy competitiveness aimed at inspiring stakeholders to innovate and augment effectiveness. Comment. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की स्थापना की गई।

इसके प्रमुख उद्देश्य
- स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
- उपभोक्ता हित
- नवाचारों को अपनाना
- मोनोपॉली रोकना

CCI की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में भूमिका

● हितधारकों के दृष्टिकोण से

(A) उपभोक्ता हित :-
- स्वच्छ व स्वस्थ उत्पादों तक पहुँच
- MRP से अधिक मूल्य नहीं
- फ्राड विज्ञापन पर रोक (सोशल मीडिया विज्ञापन भी शामिल)

(B) कंपनी अथवा निर्माता की दृष्टिकोण से

- तानाशाही पर रोक
- सभी को समान अवसर (व्यापार हेतु)
- व्यापार की कुप्रथाएं रोकना। (उदा) → डीप डिस्काउंट द्वारा बाजार में मोनोपोली की स्थापना।

(C) छोटे व्यापारियों व खुदरा व्यापारिक दृष्टिकोण से

- अनु० 19(1)-g का अनुपालन (पेशे का अधिकार)
- e-कॉमर्स की फेक डिस्काउंट प्रणाली पर रोक लगाना। (उदा० अमेजन पर CCI का आदेश।)

CCI द्वारा नवाचार हेतु किए गए अन्य प्रयास

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

① e-तकनीकी व e-कॉमर्स हेतु ONDC (ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) की शुरुआत

② MSMEs की e-कामर्स तक पहुँच बढ़ाना ⇒ समान अवसर उपलब्ध होना

③ MNC - e कॉमर्स कंपनियों पर इन्वेंटरी मॉडल के तहत FDI पर रोक

④ e-कॉमर्स स्वयं किसी कंपनी (प्रोडक्ट निर्माता) में अधिकतम 25% हिस्सा रख सकती है।

इस प्रकार CCI द्वारा आधुनिकृत तकनीकियाँ अपनाकर व्यापार तथा व्यवसाय प्रणाली का अधिक लोकतांत्रिकीकरण किया जा रहा है, जिससे स्वस्थ परंपरा बनी रहे।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidate must not write on this margin

2. "पेड न्यूज का खतरा अक्सर चुनावों के दौरान अपना भयावह रूप दिखाता है।" भारत में पेड न्यूज को एक चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
"The menace of paid news often rears its ugly head during elections." Discuss the need for making paid news an electoral offence in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

पेड न्यूज ऐसी न्यूज है जो बिना निष्पक्षता व रिपोर्टिंग के किसी एक व्यक्ति या समूह के प्रति अच्छी या बुरी नियत से धन के बदले न्यूज चलाई जाती है।

(उदा०) वोटिंग के दौरान विपक्षी उम्मीदवार के प्रति पूर्वाग्रह आधारित न्यूज प्रसारण करना

पेड न्यूज से उत्पन्न खतरे

① निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के विपरीत (अनु० 325 का हनन)

② उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं (धनबल ∝ पेड-न्यूज ∝ जीतने की संभावना)

③ फैक्ट चेकिंग यूनिट्स (FCU) का अभाव तथा आम जन में निम्न जागरूकता

(4) मीडिया नीति संहिता के विरुद्ध (निष्पक्ष रिपोर्टिंग)

(5) लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का ढहना

ADR की रिपोर्ट के अनुसार 17 वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक पेड न्यूज चलाई गई।

इस हेतु इसे चुनावी अपराध बनाने की आवश्यकता है ताकि

↓ निष्पक्ष चुनाव | ↓ लोकतंत्र में विश्वास | ↓ चुनावी मतदान व्यवहार | ↓ राजनीतिक अधिकार

↓

ये सभी सुरक्षित रहें।

ज्ञातव्य है कि चुनावी अपराध घोषित करने हेतु RPA-अधि० 1951 में संशोधन की आवश्यकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

चुनावी अपराध बनाने से लाभ

- मीडिया का विनियमन
- चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता (उदा० - 2016 के USA राष्ट्रपति चुनाव में कथित पेड-न्यूज सामग्री रूस द्वारा)
- अपराधी उम्मीदवार का नोमिनेशन खारिज होना।
- राजनीति का अपराधीकरण कम होना। (वर्तमान में 43%)

अतः पेड-न्यूज को चुनावी अपराध में शामिल कर ECI को अधिक शक्ति प्रदान कर चुनावी शुचिता को बेहतर बनाया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

13. भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, न्यायालयों द्वारा उद्धृत 'अनिवार्यता के सिद्धांत' पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Discuss the 'Doctrine of Essentiality' referred to by the courts in the context of religious practices in India. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों इस हाशिए नहीं लिखन चाहिए
Candida must not write on this mar

अनिवार्यता के सिद्धांत को सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने 1960 के दशक में दिया।

अनिवार्यता का सिद्धांत

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक पूर्ण व निरपेक्ष अधिकार नहीं है तथा कौन सी प्रथा धार्मिक प्रथाओं का अनिवार्य अंग है और कौनसा इसका अंग नहीं है, इसका निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसे ही अनिवार्यता का सिद्धान्त कहा गया।

इसके द्वारा निम्न पर बल दिया गया

① धार्मिक स्वतंत्रता (अनु० 25-28) V/s
व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर

② समानता व संवैधानिक आदर्श V/s
धार्मिक मूल्यों पर

न्यायालय का रुख

→ यदि धार्मिक प्रथाएँ अनुच्छेद
14, 15, 19 या 21 का हनन करें तो
उसे अनिवार्य धार्मिक प्रथा
नहीं माना जाएगा।

उदा० सुप्रीम कोर्ट के निर्णय
→ शायरा बानो वाद (1986)
→ सबरीमाला वाद (2017)
→ तीन तलाक (शाह बानो) वाद

इनमें लिंग के आधार पर विभेद
पर प्रतिबंध (अनु० 15) को प्रभावी
बनाने पर बल दिया गया।

इसकी प्रासंगिकता

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

→ महिला सशक्तिकरण
→ सामाजिक रूढ़िवादिता की जगह गतिशीलता पर बल
→ समावेशी समाज निर्माण पर बल
→ संवैधानिक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय (अनु० 38) हेतु

~~इस~~ प्रकार

चुनौती
- न्यायिक सक्रियता
- शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध (अनु० 50)
- धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध (अनु० 25)

इस प्रकार अनिवार्यता का सिद्धांत गतिशील व समावेशी समाज निर्माण व धार्मिक पक्षों में संतुलन हेतु एक प्रगतिकारी कदम है।

उम्मीदवारों इस हाशिए नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सरकार के आकार को सीमित करने की तत्काल आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

As per the recently released report of the Economic Advisory Council to the Prime Minister (EAC-PM), there is an urgent need to limit the size of the government in India. Do you agree? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सरकार के आकार को सीमित करने का तात्पर्य अधिकतम गवर्नेंस - न्यूनतम सरकार है।

इसमें सरकार के सभी स्तरों यथा कार्यपालिका, प्रशासन व न्यायिक स्तर पर आकार कम करने की गुंजाइश है।

सरकार को सीमित करने की आवश्यकता का प्रमुख कारण

① उच्च राजस्व व्यय :- यह राजस्व प्राप्ति से भी अधिक है अत: FRBM अधि० का पालन नहीं।

② समय के सापेक्ष कम आवश्यकता : तकनीकी विकास - रोबोटिक्स, AI, ML, डेटा एनालिसिस इत्यादि के कारण मैनुअल कार्य में कमी

③ राज्यों की बिगड़ती राजकोषीय व्यवस्था :- जैसे तेलंगाना व राजस्थान में 50% राजस्व व्यय केवल पेंशन वितरण में

④ अधिक संचार चैनल से निर्णय क्रियान्वयन में देरी (वेबेरियन मॉडल)

⑤ बढ़ता भ्रष्टाचार, नवाचार की कमी तथा बदलावों के प्रति अनमना प्रवृत्ति

इससे उत्पन्न चुनौतियाँ

① लोक कल्याणकारी राज्य की प्रकृति प्रभावित → योजनाओं का क्रियान्वयन आसान नहीं

② लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रभावित

फण्ड वितरण — फण्ड जारी

(जनता) — (प्रशासन) — (सरकार)

⇓ कड़ी का कार्य

लिंक टूटना (सरकार आकार में कमी)

⇓

संधारणीय व समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास प्रभावित होगा।

उम्मीदवारें
इस हाशिए
नहीं लिख
चाहिए
Candid
must n
write o
this ma

③ रोजगार क्षति :- PLFS आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में पहले से ही 5.1% बेरोजगारी है।

④ व्यापक जनसमर्थन का अभाव

⑤ वोट बैंक राजनीति

⑥ PSU निजीकरण का पूर्व उदाहरण लाभदायक नहीं इत्यादि

आगे की राह

→ 2nd ARC की अनुशंसा लागू करना

→ तकनीकी आधारित कार्यों में मानव बल को बैच दर बैच कम करना

→ अत्यंत कमी न करना ताकि चुनाव, जनगणना व सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली व्यवस्थित रहे।

→ निचले स्तर पर निजीकरण घटाकर नवाचार व विकास को प्रोत्साहन देना।

न्यूनतम सरकार - अधिकतम गवर्नेंस

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

15. इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना की कल्पना भारत में उच्चतर शिक्षा के 'विश्व स्तरीय' केंद्र विकसित करने के लिए की गई थी, लेकिन छह साल बाद भी, यह अभी तक गेम चेंजर नहीं बन पाई है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The Institutions of Eminence (IoE) scheme was conceived to develop 'world-class' centres of higher education in India but six years later, it is yet to become the game changer it was intended to be. Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवार इस हाशिए में नहीं लिखें चाहिए
Candidates must not write on this margin

2017-18 में शिक्षा मंत्रालय (तत्कालीन MoHRD) ने 6 विश्वविद्यालयों को IoE का दर्जा दिया था।

इसका प्रमुख उद्देश्य

→ QS रैंकिंग में टॉप 100 में भारतीय विश्वविद्यालयों को शामिल करना
→ वैश्विक स्तरीय शिक्षा केन्द्र बनाना
→ वैश्विक फैकल्टी तथा छात्रों को आकर्षित करना
→ भारत की उच्चतर शिक्षा में निवेश बढ़ाना (प्रति विश्वविद्यालय 1000 करोड़)

प्रगति

→ 3 IITs (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों) को फंड जारी
→ 3 निजी संस्थानों को UGC द्वारा स्वायत्तता प्रदान की गई

↓ प्रशासन ↓ करिकुलम ↓ फीस निर्धारण ↓ फैकल्टी चयन

लेकिन प्रगति में निम्न बाधाएँ बनी हुई है :-

① निजी निवेश की कमी (जैसे- टाटा व रिलायंस संस्था का कैंपस भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं)

② UGC द्वारा फण्ड का समय पर जारी न करना।

③ IoE में प्रवेश प्रक्रिया में असमानता उदा - [निजी वि० ⇒ कोई विशेष प्रक्रिया नह
↳ IIT हेतु JEE अधि०

④ विदेशी फेकल्टी व छात्रों का निम्न अनुपात

⑤ विश्वास का अभाव
⇓
एडमिशन प्रक्रिया गुणवत्ता की कमी

इसमें सुधार हेतु निम्न कदमों की आवश्यकता है :-

① नियमित फण्ड जारी कर प्रभाव आंकलन रिपोर्ट जारी करना।

② IoE को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जोड़ना. उदा० औद्योगिकरण 4.0 हेत

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

③ IoE में विदेशी भारतीय संस्थानों के केन्द्र को जोड़ना

(उदा०) हाल ही में IIT मद्रास के विदेशी केन्द्र (कतंजानिया) को IoE मे शामिल करना।

ज्ञातव्य है कि NEP-2020 में उच्चतर शिक्षा हेतु HECI का प्रावधान हैं जो विश्व स्तरीय केन्द्रो के निर्माण में प्रभावकारी भूमिका निभा सकता है।

उम्मीदवा इस हाशि नहीं लिख चाहिए Candi must n write o this ma

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) नवोन्मेषी और सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं की अनुमति देता है, समावेशन या पहुंच संबंधी बाधाओं को दूर करने में मदद करता है तथा रियल-टाइम डेटा की मदद से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है। उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Digital Public Infrastructure (DPI) allows for innovative and convenient public services, help overcome inclusion or accessibility barriers, and increase transparency and accountability with real-time data. Discuss with examples. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

डिजीटल पब्लिक अवसंरचना (DPI) ऐसी तकनीक आधारित अवसंरचना हैं जो इंटरनेट का प्रयोग कर मानवीय जरूरतों को आसान बनाती है

(उदा) JAM ट्रिनीटी द्वारा DBT भुगतान

DPI से होने वाले लाभ

(A) <u>नवोन्मेषी व सुविधाजनक सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँच बनाना</u> :-

(उदा) –
- टेलीमेडिसीन (<u>e-संजीवनी</u>) द्वारा होम डॉक्टर सुविधा
- NPCI द्वारा UPI के द्वारा खुदरा भुगतान को नवोन्मेषी बनाना

इससे कम समय व उच्च प्रभाविता, दक्षता तथा मितव्ययता (<u>3E</u>) द्वारा सेवाओं की प्राप्ति होती है

(B) समावेशन में DPI की भूमिका :-

→ इण्डिया स्टैक में उमंग ऐप, आधार द्वारा PDS अन्न वितरण को सभी तक पहुँचाना।
उदा० IM-PDS में आधार (AEPS) अपनाना ⇒ अंतिम छोर तक पहुँच आसान

→ बैंकिंग समावेशन हेतु जन-धन खाते का डिजिटलीकरण तथा सब्सिडी का DBT द्वारा भुगतान करना

→ NDHB के तहत e- स्वास्थ्य कार्ड द्वारा UHR (सार्वभौमिक स्वास्थ्य अधिकार की प्राप्ति)

(C) पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता में योगदान

(1) AEPS द्वारा सब्सिडी ट्रैकिंग करना

(2) भुगतान में पारदर्शिता तथा कोई लीकेज नहीं (ज्ञातव्य है कि राजीव गांधी का कथन 12 - 15 पैसे पहुँचता) अपारदर्शिता व भ्रष्टाचार को दर्शाता है।

उम्मीदवार इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(8) बैंकिंग फ्राड को रोकना

जैसे - DPI के तहत दर्पण पोर्टल तथा RBI की e-ओम्बड्समैन स्कीम

इसके बावजूद DPI के समक्ष कुछ चुनौतियाँ है जैसे

- निजता का मुद्दा (मूल अधिकार है पुट्टास्वामी वाद)
- DPI हेतु डिजिटल डिवाइड उच्च
- डिजीटल साक्षरता की कमी (ग्रामीण भारत में 15% ही)

आगे की राह

→ DPI को ब्लॉकचेन तकनीकी आधारित बनाना

→ NSDL (RBI की डिजिटल साक्षरता पर राष्ट्रीय रणनीति) को ग्रामीण बैंको (RRB) स्तर पर लागू करना

→ DPI के प्रति विश्वास सृजन जैसे- ONDC के प्रति खुदरा व्यापारियों में।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

17. कानून के अलावा, भारत में 'सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिकार' की पूर्ण प्राप्ति हेतु सामाजिक, वित्तीय और बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Besides legislation, the full realisation of the 'right to health for all' in India demands plugging of social, financial, and infrastructural gaps. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवार इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सभी के लिए स्वास्थ्य अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है। WHO के अनुसार कहीं भी, कभी भी बिना बाधा के स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तक पहुँच ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य अधिकार है।

इस हेतु कानून

1. सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति - 2017
2. स्वास्थ्य का अधिकार अधि० - 2023 (राजस्थान)
3. कार्यक्रम - PM आयुष्मान भारत योजना

ज्ञातव्य है कि मनरेगा जैसा कोई राष्ट्रस्तरीय स्वास्थ्य के अधिकार के कानून का अभाव है जो अधिकार आधारित उपागम को कमजोर करता है।

इसमें प्रमुख कमियाँ व समाधान

कमियाँ	समाधान
(A) सामाजिक बाधाएँ जैसे- स्वच्छता की कमी, जनन अस्वच्छता, संस्थागत प्रसव सीमित (ii) जनजातीय क्षेत्रों के धार्मिक पूर्वाग्रह (iii) अल्प संसाधनों की धारणा (iv) उच्च IMR & MMR	→ संस्थागत प्रसव को इंसेंटिव आधारित बनाना (जैसे- दूसरे बच्चे पर भी PM-MVY (मातृ वंदना योजना) का लाभ देना → वैक्सीन हेजिटेंसी का समाधान करना। → ASHAs तथा ANM की क्षमता निर्माण करना। → WASH रणनीति अपनाना
(B) वित्तीय कमियाँ (1) उच्च OOPE (NFHS-5 के अनुसार 48%) (2) प्रति व्यक्ति निम्न आय (3) उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं तक निम्न पहुँच	→ निःशुल्क विधिक स्वास्थ्य अधिकार की गारंटी देना → आयुष्मान भारत योजना में प्राथमिक देखभाल को शामिल करना। → PM जन औषधि केंद्रों को सभी पंचायतों में खोलना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(E) बुनियादी ढाँचे की कमी :	→ डॉक्टरों की नियमित भर्ती करना
(i) PHC में आधुनिक मशीनों का अभाव	→ PHC को केन्द्र में रखना
(ii) CHC की निम्न गुणवत्ता	→ वर्तमान GDP के 1.5% से व्यय बढ़ाकर 2.5% करना
(iii) डॉक्टर संख्या कम (WHO = 1:1000, भारत = 1:1456)	→ X-ray, NMR, MRI जैसी आधुनिक मशीनों में निवेश बढ़ाना
(iv) PMS (पैरामेडिकल स्टॉफ) की कमी	

इस प्रकार UHC की प्राप्ति तथा SDG3 के 2030 तक के लक्ष्यों में भारत प्रगति हासिल कर सकता है।

उम्मीदवा… इस हाशि… नहीं लि… चाहिए Candi… must… write… this m…

विधायी समर्थन के बावजूद 'थर्ड जेंडर' को अभी तक भारतीय समाज में मान्यता नहीं मिली है। विश्लेषण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The 'third gender' has not yet been engendered in the Indian society despite legislative nudge. Analyse. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

थर्ड जेंडर को सामान्यतया LGBTQ+ की संज्ञा दी जाती है जो अपने लिंग के प्रति विपरीत व्यवहार को दर्शाते हैं। इनकी सामाजिक स्थिति दयनीय होने के कारण सर्वाधिक वंचन वाला समुदाय है।

विधायी समर्थन → नवतेज सिंह जोहर वाद - 377 को समाप्त

→ ट्रांसजेण्डर (अधिकारों को मान्यता) अधि॰ 2020 :- इसमें निम्न प्रावधान थे
→ ट्रांसजेण्डर परिषद की स्थापना
→ शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार सहित विभेद से प्रतिषेध (अनु॰ 15 का पालन)
→ सार्वजनिक परिवहन में विभेद पर रोक
→ ट्रांसजेण्डर कल्याण बोर्ड व फण्ड का निर्माण

इसके बावजूद समाज में इन्हें मान्यता मिलने में अनेक चुनौतियाँ मिल रही

① सामाजिक कलंक के रूप में देखना।
② अशोभनीय शब्दों का प्रयोग (जैसे SC ने इस पर रोक लगाने के बावजूद)
③ पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के विपरीत होना
जैसे- परिवार में विपरीत लिंग भावों को ग्राह्य माना गया है
④ इनके सामाजिक दबाव समूह के रूप में उपस्थिति की कमी
⇓
इससे वोटबैंक राजनीति पर भी कोई प्रभाव नहीं
⑤ समाज में आधुनिक मूल्यों को अपनाने में धीमापन
⑥
अन्य कारण —
→ भेदभाव
→ अस्पृश्यता
→ हीनता का भाव
→ वंचन

इसके समाधान हेतु प्रयास

उम्मीद... इस हा... नहीं लि... चाहिए Cand... must write this m...

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

→ सामाजिक समावेशीता हेतु अनु० 15 का सफल क्रियान्वयन करना
→ स्कूली शिक्षा स्तर पर ही इनके अधिकारों को मान्यता दे।
→ स्व निर्धारण पद्धति को अधिक सकुशल बनाना।

ज्ञातव्य हैं कि LGBTQ+ के समलैंगिक विवाह पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के मत भी अधिक उदार व प्रगतिशील है जिससे इन्हें मानवाधिकार तथा ICCPR की प्राप्ति सुनिश्चित होगी।

19. अन्य कारकों के अलावा, चीन और पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों ने भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) से अपनी अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन बना दिया है। विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
Among other factors, strained ties with China and Pakistan make it difficult for India to fulfill its expectations from the Shanghai Cooperation Organisation (SCO). Discuss. (Answer in 250 words) 15

उम्मीद... इस ह... नहीं लि... चाहिए
Cand... must write this n...

भारत 2016 में शंघाई कॉपरेशन संगठन का सदस्य बना तथा पाकिस्तान भी 2016 में इसका सदस्य बना।

SCO की प्रासंगिकता :-

43% जनसंख्या ; 20% GDP के साथ वैश्विक व्यापार में करीब 18% योगदान रखता है।

SCO की अपेक्षाएँ

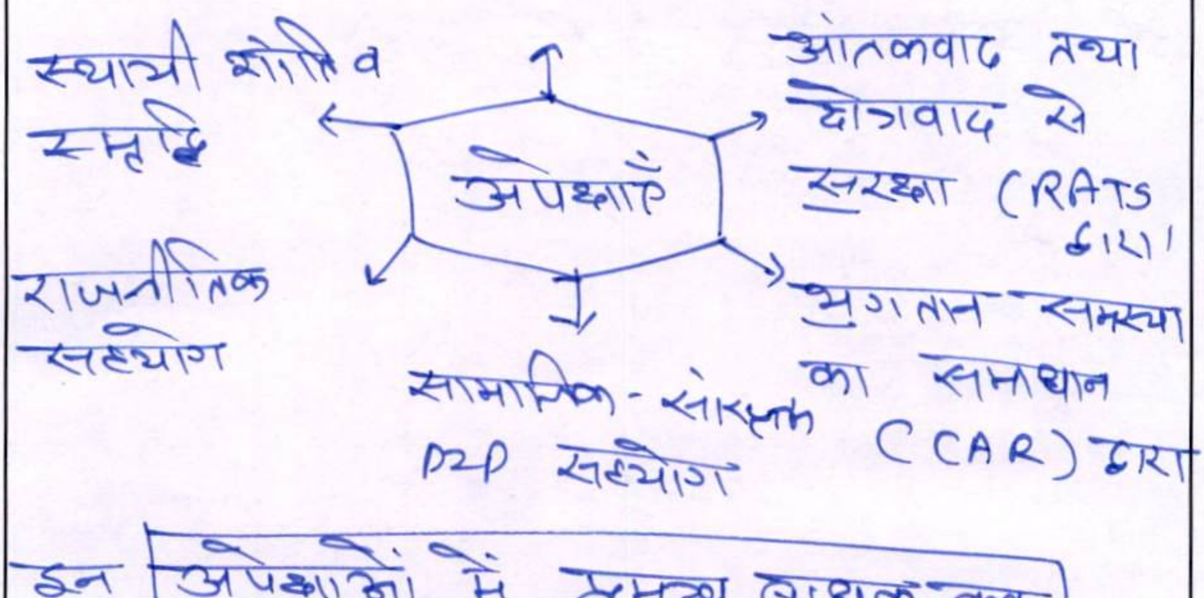

इन अपेक्षाओं में प्रमुख बाधक तत्व

① भारत-पाक तनावपूर्ण संबंध

- कश्मीर का मुद्दा
- कट्टरवाद व आतंकवाद
- ISI द्वारा घुसपैठ का मुद्दा
- आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप

② भारत-चीन तनावपूर्ण संबंध

(i) सीमा तनाव:-

तवांग (अरुणाचल).
गलवान विवाद,
डोकलाम (2017)
विवाद इत्यादि

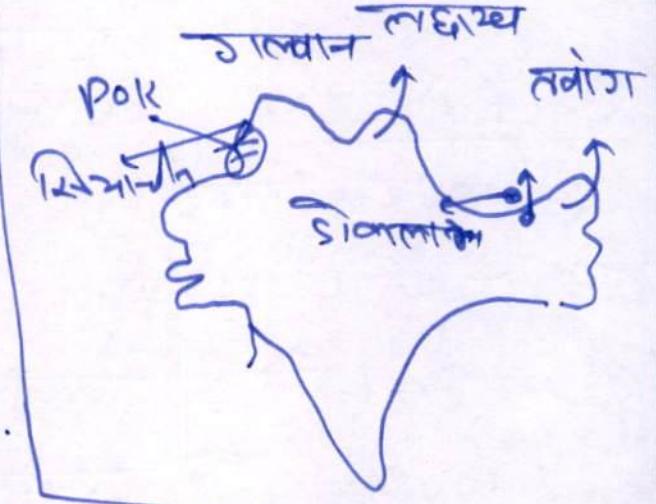

② व्यापार विवाद:..

भारत $100 बिलियन व्यापारिक घाटे का सौदा

③ संप्रभुता तथा चीनी विस्तारवादी नीति:- IOR, इंडो पैसिफिक, डेटट्रैप, मोतियों की माला तथा 9-डैश लाइन द्वारा दक्षिणी चीन महासागर में मुद्दे

अन्य कारक

- → रूस-यूक्रेन युद्ध
- → SCR (सप्लाई चेन बाधा)
- → अफगानिस्तान समझौते का पूर्ण लागू न होना
- → मध्य एशिया में USA के हित

इसके बावजूद **SCO की सफलताएँ**

① RATS की स्थापना तथा डाटा का साझाकरण।

② स्थायी सचिवालय (बीजिंग) की स्थापना

③ BOP हेतु रिजर्व फण्ड की व्यवस्था (covid-19 के समय कजाकिस्तान की सहायता)

④ भारत-चीन तथा भारत-पाक वार्ताओं का मंच प्रदान (इससे भारत-चीन रिश्तों पर निरन्तर वार्ता जारी)

उल्लेखनीय है कि 2023 की SCO अध्यक्षता भारत के पास है अतः भारत को बहुपक्षवाद, सुधार, आतंकवादरोधी तथा संप्रभुता जैसे मुद्दों को प्रमुखता से रखना चाहिए।

उम्मी
इस ह
नहीं
चाहिए
Can
must
write
this r

संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी (iCET) पर हाल ही में संपन्न पहल, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनकी साझेदारी में लंबे समय से प्रतीक्षित परिवर्तन का वादा करती है। परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The recently concluded initiative on Critical and Emerging Technology (iCET) between the United States and India promises a long overdue transformation of their partnership in the field of technology. Examine. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत- USA संबंधों में अनेक तत्वों के साथ तकनीकी विकास व हस्तांतरण एक विशेष मुद्दा है जिस पर हाल मे iCET पहल व साझेदारी समझौता किया गया।

iCET पहल

→ USA द्वारा तकनीकी हस्तांतरण व सहायक सेवाएँ

→ AI तथा ML क्षेत्र में MoU
बिग डेटा एनॉलिटिक्स में सहायक

→ रक्षा प्रौद्योगिकी भागीदारी
भारत को प्रमुख रणनीतिक रक्षा भागीदार की संज्ञा दी गई

→ उभरती अन्य तकनीकि- रोबोटिक्स, नैनोतकनीकी तथा क्वांटम तकनीकी सहयोग समझौता

उम्मी...
इस ...
नहीं ...
चाहिए...
Can...
must...
write...
this ...

पहल का महत्व

- तकनीकी निवेश बढ़ना

महत्व

- रणनीतिक बल
- iCET क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाना।
- तकनीकी निर्यात बढ़ना
- USA की तकनीक तथा भारत के IT कौशल का अभिसरण करना
- नए रोजगार अवसरों का सृजन

ज्ञातव्य है कि भारत-USA तकनीकी (मुख्यत: CET) पर समझौते पर वार्ता 2011 से चली आ रही थी।

अभी तक केवल —
- नाभिकीय ऊर्जा
- स्वच्छ ऊर्जा
- लॉजिस्टिक सेवाओं

→ पर ही समझौते थे

इस iCET पहल में शामिल मुद्दे

① आयात बढ़ना :- USA द्वारा तकनीक बेचना। जैसे रक्षा तकनीक का निर्यात करना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

② USA के रणनीतिक हितो के अनुकूल :-
जैसे- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना। (पनडुब्बी द्वारा)

③ ब्रेन निष्कर्षण सिद्धान्त के अनुकूल
जैसे- भारतीय पेशेवर → USA में
↓
तकनीक का विकास → भारत को ← बन्धना ← CAD (घाटा बढ़ना)

इसके बावजूद इसके निम्न लाभ है.

① भारतीय IT उद्योग हेतु लाभकारी
② स्पेस वारहेड में ML, रोबोटिक्स सहायक
③ IOR में नेट सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भागीदारी बल
④ SAGAR रणनीति के अनुकूल।

अतः Indo USA iCET
पहल दोनो देशो के मध्य भू-राजनीतिक सिद्धांतो को मजबूत करेगा।

SPACE FOR ROUGH WORK